

## आम चुनाव 2024 और गठबंधन सरकार

### प्रलिस के लयः

गठबंधन सरकार, [आर्थिक सुधार](#), [संघीय प्रणाली](#), [राजकोषीय उत्तरदायतल और बजट प्रबंधन \(FRBM\)](#), [प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना](#), [सूचना प्रौद्योगिकी अधनलनल, 2000](#), [शकषा का अधकार अधनलनल](#), [सूचना का अधकार अधनलनल](#), [भोजन का अधकार](#), [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनलनल \(MGNREGA\)](#), [आधार](#), [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\)](#)

### मेन्स के लयः

गठबंधन सरकार के गुण और दोष, गठबंधन सरकारों की चुनौतललें

[स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यलें?

हाल ही में 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार एक दशक तक लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सरकार में वापस आई है।

- हालाँक, यह परणलम एक पार्टी के प्रभुत्व के अंत का संकेत देता है और केंद्र में एक गठबंधन सरकार की वापसी का संकेत देता है।

## गठबंधन सरकार क्या है?

### परचयः

- गठबंधन सरकार को इस प्रकार परभाषलत कयल जाता है कजब कई राजनीतिक दल मलकर सरकार बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं।
- आधुनिक संसदों में गठबंधन आमतौर पर तब होता है जब कसल एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मलता।
- यदलनलरलवाचतल सदस्यों के बहुमत वाली कई पार्टललें अपनी नीतललें से बहुत अधकल समझौता कयल बना एक साझा योजना पर सहमत हलें, तो वे सरकार बना सकती हैं।

### गठबंधन सरकार की वशलषताएँ:

- गठबंधन का तात्पर्य सरकार बनाने के लयल कम-से-कम दो पार्टललें के असत्तलव से है।
  - गठबंधन राजनीतल की पहचान वचलरधारा नहीं बलकल वयावहारकलता है।
- गठबंधन की राजनीतल स्थलरल नहीं बलकल गलतशील मामला है क्यलेंक गठबंधन के घटक और समूह वधलतल हो जाते हैं तथा नए समूह बनाते हैं।
- गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करतल है, जो गठबंधन के सभी सदस्यों की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती।

### चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात् गठबंधनः

- चुनाव पूर्व गठबंधन काफी लाभदायक होते हैं क्यलेंक यलह पार्टललें को संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर मतदाताओं को लुभाने के लयल एक साझा मंच प्रदान करता है।
- चुनाव-पश्चात् संघ का उद्देश्य मतदाताओं को राजनीतिक सत्ता साझा करने तथा सरकार चलाने में सक्षम बनाना है।

## गठबंधन पर पुंछी और सरकारयल आयोग की सफलरशलें:

- पुंछी आयोग की संसुतलः पुंछी आयोग ने स्पष्ट नयलम स्थापतल कयल कल राज्यपालों को त्रशलंकु वधलनसभाओं में मुख्यमंत्रललें की नयुक्तल कसै करनी चाहयल। ये दशल-नरलदेश राष्ट्रपतल के लयल भी लागू हैं:
  - जसल पार्टी या पार्टललें के गठबंधन को वधलनसभा में वयापक समर्थन प्राप्त हो, उसे सरकार बनाने के लयल आमंत्रतल कयल जाना चाहयल।
  - यदलकोई चुनाव पूर्व समझौता या गठबंधन पर आधारतल है, तो उसे एक राजनीतिक दल माना जाना चाहयल और यदल ऐसे गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, तो ऐसे गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लयल बुलाया जाएगा।

◦ यदि किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल को यहाँ दर्शाए गए वरीयता क्रम के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिये।

- चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाले दलों का समूह सबसे अधिक सीटें जीतता है।
- सबसे बड़ी पार्टी द्वारा अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा।
- चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें सभी सहयोगी सरकार में शामिल होंगे।
- चुनाव-पश्चात् गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होंगे तथा शेष दल नरिदलीय होंगे, जो सरकार को बाह्य समर्थन प्रदान करेंगे।

■ सरकारिया आयोग ने पाया था कि भारतीय संघवाद में समस्याएँ केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श तथा संवाद की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं।

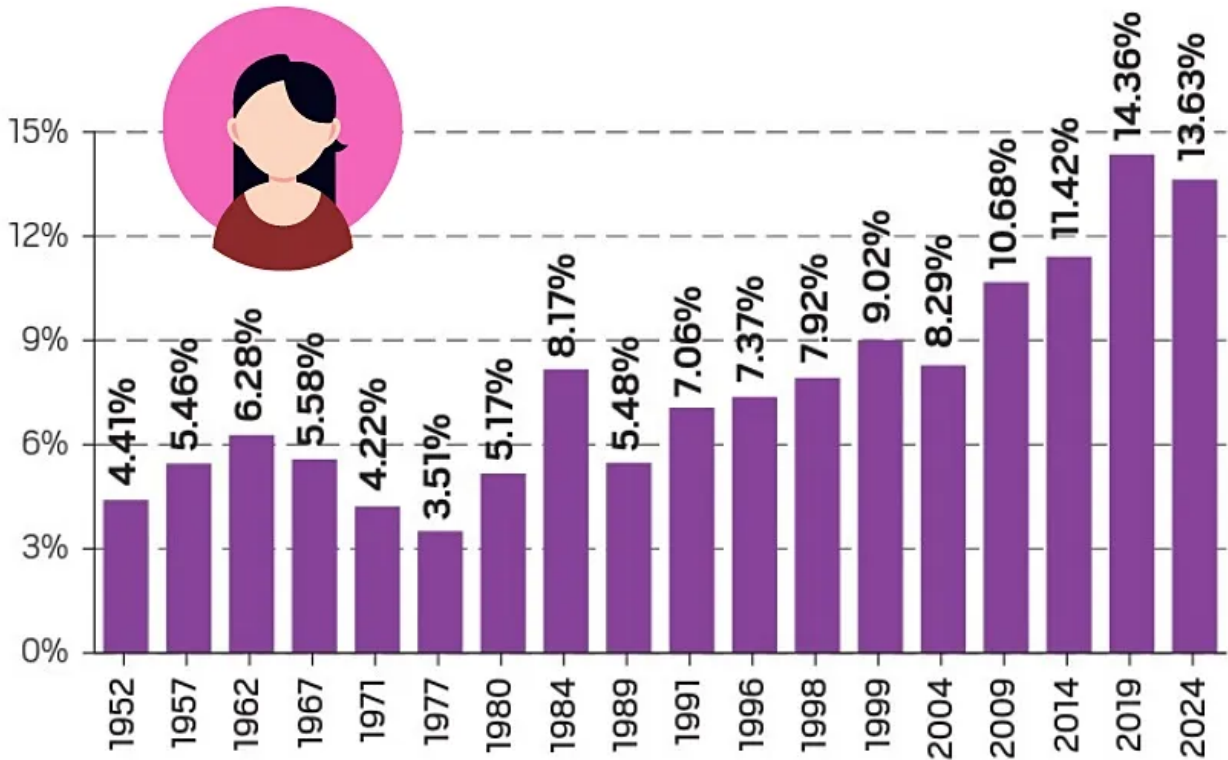
◦ यह पाया गया कि अंतर-राज्यीय परिषद ने तब कार्य किया जब राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका थी। यह गठबंधन सरकार की भूमिका को दर्शाता है जिसमें क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

## 2024 के आम चुनाव में अन्य घटनाक्रम:

■ महिलाएँ:

- भारत ने वर्ष 2024 के आम चुनाव में **लोकसभा** के लिये 74 महिला सांसदों को चुना है, जो वर्ष 2019 की तुलना में चार कम और वर्ष 1952 में भारत के पहले चुनावों की तुलना में 52 अधिक है। सर्वाधिक 11 महिलाएँ पश्चिम बंगाल से चुनकर आई हैं।
- ये 74 महिलाएँ नचिले सदन की नरिवाचति संख्या का मात्र 13.63% हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या 46%, बरटिन में 35% तथा अमेरिका में 29% है।
- इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला **प्रधानमंत्री** रही हैं।

## CHANGE IN WOMEN'S STRENGTH IN LOK SABHA OVER THE YEARS



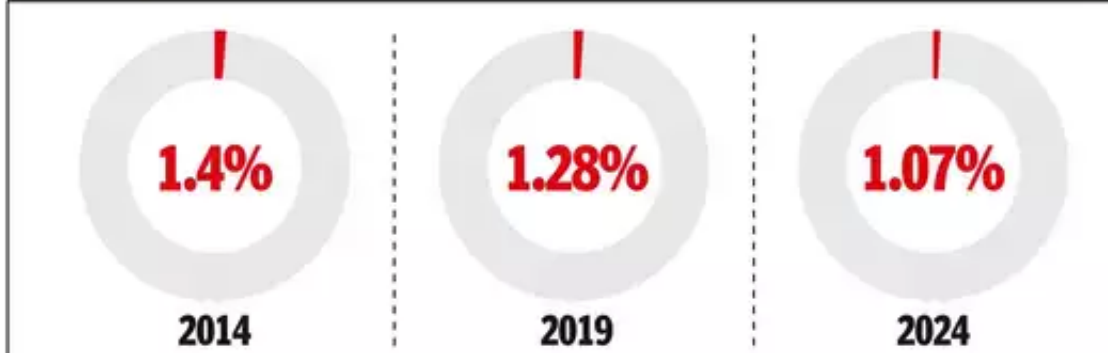
//

■ नोटा:

- इंदौर विधानसभा में 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए।
  - यह किसी भी लोकसभा नरिवाचन क्षेत्र में अब तक नोटा को मलि सर्वाधिक वोटों की संख्या है।
- नोटा का विकल्प पहली बार वर्ष 2014 के आम चुनावों में पेश किया गया था।
- नोटा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि यदि किसी सीट पर सबसे अधिक वोट नोटा को मलि हों, तो दूसरा सबसे सफल उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है।

- हरियाणा में नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना गया है।

## STATE NOTA PERCENTAGE



### TOP 5 THIS YEAR

	NOTA	Total voters	Percentage
DINDIGUL	22,120	11,43,196	1.93%
SRIPERUMBUDUR	26,450	14,35,243	1.84%
TENKASI	17,165	10,31,961	1.66%
TIRUPPUR	17,737	11,35,998	1.56%
CHENNAI CENTRAL	11,163	7,28,614	1.53%

## गठबंधन सरकार के गुण और दोष क्या हैं?

### ■ गुण:

- गठबंधन सरकार विभिन्न दलों को एक साथ लाकर **संतुलित नरिणय** लेती है तथा विभिन्न हतिधारकों के **हतियों को संतुष्ट** करती है।
- भारत की विविध संस्कृतियों, भाषाएँ और समूह, गठबंधन सरकारों को एकदलीय सरकारों की तुलना में **अधिक प्रतिनिधिक** एवं लोकप्रिय जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं।
- गठबंधन की राजनीति, एकदलीय सरकार की तुलना में क्षेत्रीय ज़रूरतों के प्रति अधिक सजग रहकर **भारत की संघीय प्रणाली** को मज़बूत बनाती है।

### ■ दोष:

- ये अस्थिर हैं क्योंकि गठबंधन सहयोगियों के बीच नीतिगत मुद्दों पर असहमति होने के कारण सरकार गिर सकती है।
- गठबंधन सरकार में **प्रधानमंत्री** का अधिकार सीमति होता है क्योंकि महत्त्वपूर्ण नरिणय लेने से पहले उन्हें गठबंधन सहयोगियों से परामर्श करना आवश्यक होता है।
- गठबंधन सहयोगियों के लिये 'सुपर-कैबिनेट' की तरह संचालन समिति, शासन में **कैबिनेट** के अधिकार को सीमति करती है।
- गठबंधन सरकार में छोटी पार्टियों संसद में अपने पात्रता से अधिक की मांग करके महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।
- क्षेत्रीय दलों** के नेता अपने क्षेत्र के वशिष्ट मुद्दों की वकालत करके राष्ट्रीय नरिणयों को प्रभावित करते हैं तथा गठबंधन वापसी के खतरे के तहत अपने हतियों के अनुरूप कार्य करने के लिये केंद्र सरकार पर दबाव डालते हैं।
- गठबंधन सरकार में, गठबंधन में शामिल सभी प्रमुख दलों के हतियों के कारण **मंत्रपरिषद** का वस्तितार होता है।
- गठबंधन सरकारों में, सदस्य अक्सर एक-दूसरे पर दोषारोपण करके गलतियों की ज़िम्मेदारी लेने से बचते हैं, इस प्रकार सामूहिक और व्यक्तिगत **जवाबदेही** दोनों से बचते हैं।

## सुधारों में गठबंधन सरकारों की भूमिका क्या रही है?

### ■ ऐतिहासिक संदर्भ:

- वर्ष 1991 के बाद से भारत में गठबंधन सरकारें देखने को मिली हैं, जहाँ अग्रणी पार्टियाँ बहुमत के आँकड़े यानि 272 सीटें प्राप्त करने से काफी दूर रही हैं।
- गठबंधन सरकारों ने भारत के इतिहास में कुछ सबसे साहसिक आर्थिक सुधार लागू किये हैं।

### ■ पछिल्ली गठबंधन सरकारों द्वारा किये गए उल्लेखनीय सुधार:

- पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार (1991-1996):
  - आर्थिक उदारीकरण (LPG सुधार): इस सरकार में [लाइसेंस-परमिट राज](#) को हटाकर अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को अपनाया गया।
  - विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता: भारत [विश्व व्यापार संगठन \(World Trade Organisation\)](#) का सदस्य बन गया, जिससे वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक गहनता से एकीकृत हो गया।
- देवेगौड़ा सरकार (जून 1996-अप्रैल 1997):
  - ड्रीम बजट: इन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर कर दरों को कम करने तथा करदाताओं एवं व्यवसायिकों के लिये अधिक अनुकूल आर्थिक माहौल को बढ़ावा देने के लिये जाना जाता था।
- अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (मार्च 1998-मई 2004):
  - राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility & Budget Management- FRBM) अधिनियम: सरकारी उधारी को सीमित करके राजकोषीय अनुशासन लागू किया गया।
  - वनिविश और बुनियादी ढाँचा: घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपकरणों के वनिविश पर जोर दिया गया तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार किया गया।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र के तेज़ी से विकास के लिये आधार तैयार किया गया।
- मनमोहन सहि सरकार (2004-2014):
  - अधिकार-आधारित सुधार: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भोजन का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MG-NREGA) जैसे विभिन्न सुधारात्मक उपाय लिए गए।
  - आर्थिक वनियमन: ईंधन की कीमतों को वनियमन मुक्त किया गया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आरंभ किया गया तथा आधार (Aadhaar) और GST प्रणालियों पर कार्य किया गया।

## नषिकर्ष:

- अंतरनहिति चुनौतियों के बावजूद, गठबंधन सरकारें विविध मतों के लिये एक मंच प्रदान करती हैं और सर्वसम्मति से संचालित नीतियों को बढ़ावा दे सकती हैं।
- पारस्परिक सम्मान, मज़बूत नेतृत्व और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की नींव पर निर्मित एक सुचारू रूप से कार्य करने वाला गठबंधन, एक जीवित लोकतंत्र की जटिलताओं से निपट सकता है।
- न्यायमूर्ति एम. एन. वैकटचलैया आयोग की रिपोर्ट में स्थायी गठबंधन का विचार सुझाया गया है।
  - रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि यह बेहतर होगा कि भारत में सभी सरकारें, सभी स्तरों पर, अनिवार्य रूप से 50 से अधिक वोट शेयर प्राप्त करें।
  - इस अनुशांसा के माध्यम द्वारा न्यायमूर्ति वैकटचलैया का तात्पर्य था कि केवल 50% से अधिक वोट शेयर वाली सरकार को ही शासन करने की आवश्यक वैधता प्राप्त होगी।

### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय संदर्भ में गठबंधन सरकारों की चुनौतियों और नहितिरथों पर विचिना कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचिार कीजिये: (2022)

1. लोकसभा के कार्य-पद्धति और कार्य-संचालन नयिमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का नरिवाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नयित करे।
2. यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कसिी प्रतियोगी का नरिवाचन या तो मुख्य वपिक्षी दल से, या शासक दल से, होगा।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की और उसके वनिरिणयों के वरिद्ध कोई अपील नहीं हो सकती।
4. उपाध्यक्ष की नयिकृति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा वधिवित समर्थित होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 3 और 4
- (d) केवल 2 और 4

उत्तर: (b)

**??????:**

प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को नश्विचति करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021)

प्रश्न. आपके वचिार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने कसि प्रकार से भारत में महासंघ को कसि सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणति करने के लयि कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजयि। (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/general-election-2024-and-coalition-government>

